भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3001
06 अगस्त, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

परिवार नियोजन कार्यक्रम

3001. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ग्रामीण जनसंख्या में परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रमों तथा इस प्रयोजन के लिए दिए गए विज्ञापनों पर कितनी निधियां व्यय की गई;
(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान जन्म दर में कमी के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;
(ग) गत पांच वर्षों के दौरान विशेषकर देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में नए परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;
(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन के लिए किए गए वित्तीय आवंटन और इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क): सरकार द्वारा परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में शुरू किए गए कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

i. परिवार नियोजन मीडिया अभियान: गर्भनिरोधक मांग उत्पन्न करने के लिए एक समग्र मीडिया अभियान चलाया जा रहा है।
ii. विश्व जनसंख्या दिवस और पखवाड़े और पुरुष नसबंदी पखवाड़ा प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों / राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
iii. मिशन परिवार विकास के तहत, उच्च प्रजनन वाले जिलों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल प्रचार वैन, एडवोकेसी मीटिंग, सास बहू सम्मेलन जैसी गतिविधियों का प्रचार और नई पहल किट का वितरण किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा किया गया व्यय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुलग्नक में दिया गया है

(ख): जन्म दर 2016 में 20.4 से घटकर 2018 (एसआरएस) में 20.0 हो गई है।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य प्रणालियों वाले एक ऐसे दृष्टिकोण का अनुपालन करता है, जिसमें स्टैंड एलोन परिवार नियोजन केन्द्र के बजाय परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों के जरिए आरएमएनसीएएच +एन (प्रजनन मातृत्व नवजात और किशोर स्वास्थ्य + पोषण) कार्यनीति के एक एकीकृत घटक के तौर पर प्रदान की जाती हैं।

अनुलग्नक

सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जागरूकता कार्यक्रमों पर किया गया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यय

क्र.सं.	राज्य	लाख रु. में		
		2018-19	2019-20	2020-21
		व्यय	व्यय	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.5	1.2	1.9
2	आंध्र प्रदेश	0.0	59.8	81.4
3	अरुणाचल प्रदेश	52.1	65.6	54.8
4	असम	422.3	404.7	287.6
5	बिहार	850.5	1608.2	772.2
6	चंडीगढ़	0.6	0.0	0.2
7	छत्तीसगढ़	324.6	402.1	289.8
8	दादरा और नगर हवेली	10.1	1.1	0.7
9	दमन और दीव	5.5	0.7	
10	दिल्ली	38.3	46.5	27.0
11	गोवा	7.7	16.6	8.9
12	गुजरात	415.8	487.3	435.9
13	हरियाणा	62.1	112.7	70.1
14	हिमाचल प्रदेश	272.2	135.1	198.4
15	जम्मू और कश्मीर	86.6	49.6	128.3
16	झारखंड	328.0	580.9	453.2
17	कर्नाटक	889.5	1546.1	837.5
18	केरल	101.6	126.0	412.8
19	लद्दाख	0.0	0.0	0.0
20	लक्षद्वीप	2.3	0.6	0.2
21	मध्य प्रदेश	239.0	362.9	611.6
22	महाराष्ट्र	618.9	603.8	1112.7
23	मणिपुर	10.7	345.6	10.5
24	मेघालय	57.9	61.3	125.9
25	मिजोरम	7.9	8.0	18.1
26	नगालैंड	23.2	38.7	43.5
27	ओडिशा	329.5	517.8	481.5
28	पुदुच्चेरी	3.2	22.2	11.2
29	पंजाब	229.5	89.0	79.3
30	राजस्थान	1246.8	302.3	1069.4
31	सिक्किम	18.3	1.9	0.0
32	तमिलनाडु	133.7	581.4	190.2
33	तेलंगाना	45.0	11.0	33.9
34	त्रिपुरा	20.8	25.7	19.5
35	उत्तर प्रदेश	2172.9	1723.6	2038.9
36	उत्तराखंड	151.5	98.8	130.2
37	पश्चिम बंगाल	203.5	171.2	272.8

*****